संख्या-22/2025/260 /26-3-2025- 1889039

प्रेषक,

रजनी कान्त पाण्डेय
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण विभाग,
उ0प्र0,लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः २८ जनवरी 2025

विषयः- राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास जनपद-बस्ती में छात्रावास भवन के मरम्मत/अनुरक्षण कार्यो हेतु स्वीकृत धनराशि से कराये गये कार्यो का उपभोग प्रमाण पत्र, गुणवत्ता प्रमाण पत्र एवं फोटो ग्राफ्स प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2205/स0क0/विकास/छात्रावास/252/2024-25, दिनांक-दिनांक-11.12.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें,जिसके माध्यम से निम्न विवरण के अनुसार राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास भवन में मरम्मत)/अनुरक्षण कार्यो हेतु स्वीकृत धनराशि से कराये गये कार्यो का उपभोग प्रमाण पत्र, गुणवत्ता प्रमाण पत्र एवं फोटो ग्राफ्स उपलब्ध कराते हुये अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0सं0	जनपद का नाम	छात्रावास का नाम व स्थान	आगणित धनराशि	शासन द्वारा प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि	शासन द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि	अवशेष वांछित धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	बस्ती	राजकीय अनुसूचित छात्रावास (पुराना) सिविल लाइन	66.57	21.25	8.00	37.32
2	बस्ती	राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास (गैर)	65.20	21.25	8.00	35.95
3	बस्ती	राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास (बभनान)	52.54	23.74	8.00	20.80
		कुल योग	**184.31**	**66.24**	**24.00**	**94.07**

2- उल्लेखनीय है कि जनपद-बस्ती स्थित उक्त राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावासों में मरम्मत व अनुरक्षण का कार्य कराये जाने हेतु शासनादेश संख्या-150/2017/2061/26-3-2017-10(31)/2016, दिनांक 20.09.2017, संशोधित शासनादेश संख्या-172/2017/3075-26-3-2017-10 (31)/2016, दिनांक 08.11.2017 द्वारा यू0पी0स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0 लखनऊ को कार्यदायी संस्था नामित करते हुये आगणित धनराशि रू0-184.31 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में रू0-66.24 लाख तथा द्वितीय किश्त के रूप में शासनादेश संख्या-161/2019/4381/26-3-2018, दिनांक 26.06.2019 द्वारा धनराशि रू0-24.00 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0-90.24 की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है।

3- उक्त पृष्ठभूमि में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद-बस्ती स्थित राजकीय अनुसूचित छात्रावास (पुराना) सिविल लाइन, बस्ती के मरम्मत/अनुरक्षण कार्य हेतु आगणित धनराशि रू0-66.57 लाख मे से अवशेष अन्तिम किश्त की धनराशि रू0-37.32 लाख, राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास (गैर) बस्ती के मरम्मत/अनुरक्षण कार्य हेतु आगणित धनराशि रू0-65.20 लाख में से अवशेष अन्तिम किश्त की धनराशि रू0-35.95 लाख एवं राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास (बभनान) बस्ती के मरम्मत/अनुरक्षण कार्य हेतु आगणित धनराशि रू0-52.54 लाख में से अवशेष अन्तिम किश्त की धनराशि रू0-20.80 लाख अर्थात कुल आगणित धनराशि रू0-184.31 लाख (रू0 एक करोड़ चौरासी लाख इकत्तीस हजार मात्र) में से अवशेष तृतीय/अन्तिम किश्त की धनराशि रू0-94.070 लाख (रू0 चौरानबे लाख सात हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-09-राजकीय छात्रावासों/राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का अनुरक्षण-29-अनुरक्षण मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था यू0पी0सिडको लखनऊ को उपलब्ध कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि शासनादेश संख्या-150/2017/2061/26-3-2017-10(31)/2016, दिनांक 20.09.2017, संशोधित शासनादेश संख्या-172/2017/3075-26-3-2017-10 (31)/2016, दिनांक 08.11.2017 एवं शासनादेश संख्या-161/2019/4381/26-3-2018, दिनांक 26.06.2019 में वर्णित शर्तों का अनुपालन कर लिया गया है।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक-04.03.2024 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2024/बी-1-607/दस-2024-231/2024, दिनांक-19.06.2024 में निहित शर्तो एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य मद हेतु किया जायेगा अर्थात स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। उक्त कार्यो को अनुमोदित लागत की सीमान्तर्गत ही कराया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरक्त कोई अन्य धनराशि/चार्जेज नहीं दिया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

(3) प्रायोजना के कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा जी0एस0टी0 भुगतान के सम्बन्ध में तिथिवार विवरण एवं प्रामाणिक प्रपत्र जी0एस0टी0 इन्वायस सक्षम स्तर से निदेशक, समाज कल्याण विभाग के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त लेबरसेस के रूप में प्रदान की गयी धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा ।

(4) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्च कोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) निदेशक, समाज कल्याण विभाग द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के सुसंगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 04-03-2024 एवं 19-06-2024 में दी गयी व्यवस्थानुसार प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा दो-दो माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी तथा कार्यदायी संस्था द्वारा प्राप्त धनराशि का 75 प्रतिशत उपयोग करने के उपरान्त अगले 06 माह के लिए पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित कर दी जायेगी। इसका अनुपालन निदेशक, समाज कल्याण विभाग द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

(6) प्रश्नगत परियोजना में होने वाले कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(7) परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017, दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा प्रायोजना का पाईचार्ट कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को शीघ्र उपलब्ध कराया जाय। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(8) परियोजना में कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था एवं निदेशक, समाज कल्याण की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(10) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इसका अनुपालन निदेशालय, समाज कल्याण विभाग एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप निर्गत किया जाएगा। प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु विभागीय अप्रेजल कमेटी द्वारा संस्तुत मूल्यांकित धनराशि एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(11) प्रायोजना की अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति कार्यदायी संस्था/निदेशक समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रेषित मांग एवं अभिलेखों के आधार पर अवमुक्त की जा रही है। अतः यदि परियोजना के मानक एवं अन्य बिन्दुओं के सम्बन्ध में कोई सूचना भविष्य में गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स आदि सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(12) निदेशक, समाज कल्याण विभाग द्वारा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था से सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किये जायेंगे।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0-94,07,000/- (रू0 चौरानबे लाख सात हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-083 के लेखाशीर्षक-2225017890900 राजकीय छात्रावासों/राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का अनुरक्षण-29-अनुरक्षण कार्य के नामे डाला जायेगा।

उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक-04.03.2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन निर्गत की जा रही है।

Signed by भवदीय,

Rajani Kant Pandey (रजनी कान्त पाण्डेय)

उप सचिव।

Date: 28-01-2025 18:01:04

पृ0संख्या- 22 /2025/ 260 / (1)/26-3-2025 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0,प्रयागराज।
2- महालेखाकर (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- जिलाधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी,बस्ती।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 उ0प्र0शासन।
6- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक यू0पी0सिडको, लखनऊ ।
8- निदेशक, एन0आई0सी0।
9- गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(रजनी कान्त पाण्डेय)
उप सचिव।